

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1486

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

आईसीएआर द्वारा विकसित कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकी का प्रसार

1486. श्री मनीष जायसवाल:

श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री दुलू महतो:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री राजकुमार चाहर:

श्री पी.पी.चौधरी:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में राजस्थान सहित देशभर में और विशेषकर पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसानों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) द्वारा विकसित कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए क्या व्यवस्था है;
- (ख) क्या क्षेत्रीय स्तर पर उक्त मशीनरी और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने देशभर में रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों, ड्रोन और स्वचालित उपकरणों सहित आधुनिक मशीनीकरण उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू किया है;
- (ङ.) यदि हां, तो पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) उक्त प्रौद्योगिकी के सह-विकास और कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के निकायों या स्टार्ट-अप्स के साथ साझेदारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पास अपने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार प्रणाली (113 संस्थान, 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और 68 कृषि विश्वविद्यालय) के माध्यम से कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकियों के प्रसार का एक मजबूत तंत्र है। अनुसंधान संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालयों

में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अपने नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकियों और मशीनरी का विकास करते हैं। इन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVKs) द्वारा विविध कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्र (KVKs) खेत पर प्रदर्शन; किसानों और राज्य विस्तार कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; जागरूकता कार्यक्रम; किसानों के साथ बातचीत आदि के माध्यम से मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रसार करते हैं। इसके उपरांत, राज्य सरकार के विभाग राज्यों में इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हैं। प्रौद्योगिकियों के और शोधन और सुधार के लिए किसानों की प्रतिक्रियाओं को शोधकर्ताओं तक लगातार पहुंचाया जाता है। इसके अलावा, राजस्थान और पाली लोकसभा क्षेत्र सहित एक क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के समन्वय के लिए, 8 क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से भाकृअनुप (ICAR)-राज्य समन्वय भी मौजूद है।

(ख) एवं (ग) : कृषि मशीनरी को अपनाना, किसानों की सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों के साथ-साथ फसल पैटर्न के कारण भी भिन्न होता है। भाकृअनुप (ICAR) का अनुमान है कि समग्र मशीनीकरण लगभग 47% है। बीज बेड की तैयारी सबसे मशीनीकृत ऑपरेशन (70%) है, जबकि कटाई और थ्रेशिंग, चावल और गेहूं को छोड़कर कम (35% से कम) रहती है, जहां ये 60% से अधिक हैं। गेहूं में सबसे अधिक मशीनीकृत बुवाई (65%) है, तथा रोपण/प्रत्यारोपण स्तर गन्ना (25%) और चावल (35%) में मामूली रहता है। इसके अलावा, भाकृअनुप (ICAR) ने 2012 से 2023 की अवधि के लिए 19 चयनित कृषि उपकरणों/मशीनों के प्रभाव का भी आकलन किया और यह पाया कि इन उपकरणों/मशीनों से उत्पन्न कुल अधिशेष लगभग 14,071 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था जिससे लगभग 19.5 लाख कृषि परिवारों को लाभ हुआ।

(घ) एवं (ड.) : सरकार ने राजस्थान और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में रोबोटिक्स, कृत्रिम मेधा-आधारित सिस्टम, ड्रोन और स्वचालित उपकरणों सहित आधुनिक मशीनीकरण उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की हैं। ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों में कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन, नमो ड्रोन दीदी और डिजिटल कृषि मिशन शामिल हैं।

(च) : भाकृअनुप (ICAR) प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और परिनियोजन के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित करने के लिए पहल कर रहा है। इस संबंध में, भाकृअनुप (ICAR) ने पिछले 5 वर्षों में 150 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भाकृअनुप (ICAR) के संस्थान प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और डिप्लायमेंट के लिए निजी फर्मों को विकसित प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस दे रहे हैं। भाकृअनुप (ICAR) इस उद्देश्य के लिए स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
